[2020] 9 एससीआर 482

महेश्वर तिग्गा

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 635)

28 सितंबर, 2020

[आरएफ नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी, जेजे।

दंड संहिता, 1860:

उप धारा 376, 323 और 341 - अभियोजन के तहत - यह आरोप लगाते हुए कि अभियुक्त ने 4 साल पहले चाकू की नोक पर अभियोक्ता के साथ बलात्कार किया था जब वह 14 साल की थी और शादी के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जारी रखा था - के तहत सजा - नीचे की अदालतों द्वारा - सुप्रीम कोर्ट में अपील - आयोजित: अभियोक्ता की उम्र के संबंध में साक्ष्य में व्यापक भिन्नता है - निचली अदालत ने अभियोक्ता को पाया था उसके बयान के आधार पर घटना की तारीख को 14 वर्ष की आयु - उसकी उम्र के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उसके 18 वर्ष से अधिक आयु होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है - संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है - धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी की परीक्षा आकस्मिक और लापरवाह थी - एफआईआर दर्ज करने में 4 साल की देरी सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है और आरोपों की सत्यता - मामले के तथ्यों में यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ने शुरू में उसे डर के तहत रखकर उसकी सहमति प्राप्त की थी या बाद में अभियोक्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया था - अभियोक्ता की सहमति सचेत और जानबूझकर पसंद थी - दोषसिद्धि अस्थिर है।

धारा 90 - चोट के डर से दी गई सहमति सहमति नहीं है - तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है - लेकिन गलत धारणा घटना के समय के निकट होनी चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 313 के तहत एक अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का महत्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है - धारा 313 के तहत अभियुक्त को नहीं दी गई परिस्थितियों का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया: 1. अभियोक्ता ने अपने बयान में पहले यह कहते हुए कि वह घटना की तारीख को सोलह वर्ष की थी और फिर यह कहने के लिए खुद को सही किया कि वह तेरह वर्ष की थी। हालांकि उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय चाकू की नोक पर उसकी लज्जा भंग कर दी, लेकिन स्कूल के किसी भी नाम का खुलासा न तो शिकायतकर्ता ने किया है और न ही उसके माता-पिता पीडब्ल्यू 5 और 6 द्वारा। यदि अभियोक्ता किसी स्कूल में पढ़ रहा था तो इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि स्कूल रजिस्टर आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उम्र का प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। पी.डब्ल्यू.10 ने प्रतिपरीक्षा में अभियोक्ता की आयु लगभग पच्चीस वर्ष आंकी। पी.डब्ल्यू.2, अभियोक्ता के चचेरे भाई (भाई) की उम्र लगभग 30 वर्ष थी, ने गवाही दी कि वह उससे छह साल छोटी थी। इस प्रकार अभियोक्ता की उम्र के संबंध में साक्ष्य में व्यापक भिन्नता है। निचली अदालत ने अभियोक्ता को चौदह वर्ष की आयु का ठहराया, 18.08.2001 को उसके द्वारा गवाही में 20 वर्ष की आयु के रूप में प्रकट की गई आयु के आधार पर अंगूठे के नियम को लागू किया। घटना की तारीख को अभियोक्ता की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, तारीख को उसके अठारह वर्ष से अधिक आयु के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 7] [487- एच; 488-ए डी]

2. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा बेहद आकस्मिक और लापरवाह प्रकृति की थी। यह अच्छी तरह से तय है कि धारा 313 सीआर पी सी के तहत आरोपी के सामने नहीं रखी गई परिस्थितियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, और इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। एक आपराधिक मुकदमे में, एक अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का महत्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है क्योंकि यह उसे न केवल अपने बचाव को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उसके खिलाफ दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने का भी अवसर प्रदान करता

है। एक अभियुक्त द्वारा उठाया एक संभावित बचाव उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के बिना आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है. [अनुच्छेद 8 और 9] [488-ई, एच; 489-ए-बी]

नवल किशोर सिंह वि. बिहार राज्य **(2004) 7 एससीसी 502: [2004] 3 सप्ल. एससीआर 344 - पर भरोसा।**

3. एफआईआर दर्ज करने में चार साल की देरी, अपीलकर्ता द्वारा दूसरी लड़की के साथ अपनी शादी करने से सात दिन पहले के उपयुक्त समय पर, महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य ए बी सी डी ई एफ जी एच 484 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2020] 9 एससीआर अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। प्रतिपरीक्षा में अभियोक्ता की स्वीकारोक्ति के मद्देनजर मामले की पूरी उत्पत्ति गंभीर संदेह में है कि 09.04.1999 को कोई घटना नहीं हुई थी। [अनुच्छेद 10] [490-ए-बी]

4.1. रिकॉर्ड पर साक्ष्य की प्रकृति में यह धारण करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने किसी भी भय के तहत उसे रखकर शुरुआत में अभियोक्ता की सहमति प्राप्त की। आईपीसी की धारा 90 के तहत चोट के डर से दी गई सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है। आईपीसी की धारा 90 के तहत तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है। लेकिन तथ्य की गलत धारणा घटना के समय के निकट होनी चाहिए और इसे चार साल की अवधि में नहीं फैलाया जा सकता है। यह शायद ही किसी भी विस्तार की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता द्वारा सहमति उचित विचार-विमर्श के बाद उसके द्वारा बनाई गई एक सचेत और सूचित पसंद थी, यह लंबे समय तक फैली हुई थी और विरोध न करने के लिए एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ युग्मित थी। अपीलकर्ता को लिखे अपने पत्रों में अभियोजन पक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि रिश्ते के संबंध में उसके घर पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े होते थे, और उसे पीटा जाता था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभियोक्ता का एकमात्र बयान कि पहले कथित अपराध के समय उसकी सहमति चोट के डर से प्राप्त की गई थी, स्वीकार्य नहीं है। [अनुच्छेद 13, 14] [490-जीएच; 491-ए-डी]

4.2 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने कोई झूठा वादा नहीं किया या जानबूझकर विवाह की गलत बयानी नहीं की, जिससे पार्टियों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो सके। अभियोक्ता खुद विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण अपने रिश्ते में बाधाओं से अवगत थी। एक सगाई समारोह भी इस विश्वास में आयोजित किया गया था कि सामाजिक बाधाओं को दूर किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से मतभेद भी पैदा हुए कि क्या विवाह चर्च में या मंदिर में किया जाना था और अंततः विफल रहा। उपलब्ध सबूतों पर पकड़ बनाना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता, शुरुआत से ही अभियोक्ता से शादी करने का इरादा नहीं रखता था और केवल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। अभियोक्ता ने अपने पत्रों में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता का परिवार हमेशा उसके लिए बहुत अच्छा था। [अनुच्छेद 18] [492-एफ-ए

4.3 इसलिए, अभियोक्ता की सहमति एक सचेत और जानबूझकर पसंद थी, जैसा कि एक अनैच्छिक कार्रवाई या इनकार से अलग था और जो अवसर उसके लिए उपलब्ध था, अपीलकर्ता के लिए उसके गहरे बैठे प्यार के कारण उसे स्वेच्छा से अनुमति देने के लिए प्रेरित किया गया उसके शरीर के साथ स्वतंत्रता, जो सामान्य मानव व्यवहार के अनुसार केवल उस व्यक्ति को अनुमति दी जाती है जिसके साथ कोई गहराई से प्यार करता है। [अनुच्छेद 20] [493-बी-सी]

कैनी राजन वि. केरल राज्य **(2013) 9 एससीसी 113: [2013] 10 एससीआर 196; उदय वि. कर्नाटक राज्य (2003) 4 एससीसी 46: [2003] 2 एससीआर 231; के. पी. थिम्मप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 14 एससीसी 475: [2011] 4 एससीआर 200; ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वि. महाराष्ट्र राज्य और अन्य एआईआर 2019 एससी 327: [2018] 13 एससीआर 920; प्रमोद सूर्यभान पवार वि. महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) 9 एससीसी 608: [2019] 11 एससीआर 423 - पर भरोसा। 5. अपीलकर्ता को धारा 420 और 504 आईपीसी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है। आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है, आईपीसी की धारा 341 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, अभियोजन पक्ष के बयान पर विचार करते हुए कि वह अपनी**

मर्जी से 15 दिनों के लिए अपीलकर्ता के साथ रहने गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता की सजा अस्थिर है और इसे अलग रखा जाता है। अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। [अनुच्छेद 19 और 21] [493-ए-बी, जी] प्रकाश चंद वि. हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) 5 एससीसी 628: [2019] 3 एससीआर 953; विजयन वी. केरल राज्य (2008) 4 एससीसी 763; दीपक गुलाटी वि. हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 675 - संदभत है। च]

केस लॉ संदर्भ [2019] 3 SCR 953 अनुच्छेद 5 (2008) को संदर्भित 4 SCC 763 अनुच्छेद 5 (2013) को संदर्भित 7 SCC 675 अनुच्छेद 5 को संदर्भित [2004] 3 सप्ल। SCR 344 अनुच्छेद 9 पर निर्भर [2013] 10 SCR 196 अनुच्छेद 16 पर भरोसा [2003] 2 SCR 231 अनुच्छेद 16 पर भरोसा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स [2020] 9 SCR [2011] 4 SCR 200 अनुच्छेद 16 पर निर्भर [2018] 13 SCR 920 अनुच्छेद 17 पर निर्भर [2019] 11 SCR 423 अनुच्छेद 17

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार पर निर्भर है: 2020 की आपराधिक अपील संख्या 635

2004 की सीआर अपील (एसजे) संख्या 300 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.12.2018 से। श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ एडवोकेट, अनूप कुमार, सुश्री अंकिता शर्मा, सुश्री निकिता, वरुण नारंग, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री पल्लवी लंगर, रितेश खरे, एडवोकेट उपस्थित होने वाले दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **नवीन सिन्हा, जे.**

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 341 (संक्षेप में, "आईपीसी") के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए उसे जुर्माने और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ क्रमशः सात साल, एक साल और एक महीने की सजा सुनाई।

3. अभियोक्ता, पीडब्लू 9 ने 13.04.1999 को 1999 की एफआईआर नंबर 25 दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि चार साल पहले अपीलकर्ता ने चाकू की नोक पर उसकी लज्जा को अपमानित किया था। वह तब से उससे शादी करने का वादा कर रहा था और इसी बहाने उसके साथ पति-पत्नी के रूप में शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह पंद्रह दिनों तक उसके घर पर भी रही थी, इस दौरान उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए।

एफआईआर दर्ज करने से पांच दिन पहले, अपीलकर्ता ने 09.04.1999 को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। अपीलकर्ता ने उसे धोखा दिया था क्योंकि अब वह 20.04.1999 को किसी अन्य लड़की के साथ अपनी शादी करने जा रहा था। समझौते के सभी प्रयास विफल हो गए थे।

4. अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त, रांची ने सबूतों पर विचार करने पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया कि अभियोक्ता 14 वर्ष की थी जब अपीलकर्ता ने पहली बार चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया था। उसने उससे शादी करने के अपने वादे का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता को लिखे गए पत्र, उनकी तस्वीरें एक साथ और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ता का बयान दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे।

5. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, श्रीमती वी. मोहना ने प्रस्तुत किया कि चार साल बाद देर से दर्ज की गई एफआईआर स्पष्ट रूप से एक बाद में दर्ज की गई थी। आरोपों की पूरी उत्पत्ति अत्यधिक संदिग्ध और संदिग्ध है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने 09.04.1999 को उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता को लिखे गए पत्रों के साथ-साथ उसके द्वारा अपीलकर्ता को लिखे गए पत्रों को परीक्षण के दौरान प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था, जो पर्याप्त रूप से समय के साथ उनके बीच एक गहरे प्रेम संबंध को स्थापित करते हैं। अभियोक्ता की आयु लगभग 25 वर्ष थी, जैसा कि पी.डब्ल्यू.10, डॉक्टर द्वारा 14.04.1999 को उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी। अत भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से पूछे गए प्रश्न बहुत ही आकस्मिक और लापरवाह थे, जिसके कारण बचाव के उचित अवसर से इनकार किया गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से इनकार करके उसे गंभीर पूर्वाग्रह हुआ। सामाजिक कारणों से उनके बीच विवाह नहीं हो सका क्योंकि अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति का था, जबकि अभियोक्ता ईसाई था। प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2019) 5 एससीसी 628, विजयन बनाम केरल राज्य, (2008) 4 एससीसी 763, कैनी राजन बनाम केरल राज्य, (2013) 9 एससीसी 113, दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7

एससीसी 675 और उदय बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 4 एससीसी 46 पर भरोसा किया गया था।

6. . राज्य के विद्वान वकील सुश्री प्रज्ञा बघेल ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान आरोपों के साथ खड़ा था। एफआईआर दर्ज करने में देरी को समझौता प्रयासों के कारण पर्याप्त रूप से समझाया गया है जो अमल में लाने में विफल रहे। पीडब्ल्यू 7, अभियोक्ता की बहन ने भी पुष्टि की थी कि बाद में अपीलकर्ता द्वारा चाकू की नोक पर यौन उत्पीड़न किया गया था और वह रोते हुए घर आई थी। अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को उसकी अनुपस्थिति में चुप रहने के लिए कहा था, यह खुलासा करते हुए कि उसके इरादे नेक नहीं थे। सहमति से संबंध का बचाव अप्रासंगिक है क्योंकि अभियोक्ता चौदह वर्ष की आयु का था। अपीलकर्ता ने केवल शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए शादी का झूठा वादा किया था। शुरू से ही उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और उन्होंने झूठी गलत बयानी से अपीलकर्ता की सहमति प्राप्त की, जो कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है। अभियोक्ता के साक्ष्य विश्वसनीय हैं।

7. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अभियोक्ता ने अपने बयान में पहले कहा गया है कि वह घटना की तारीख को सोलह साल की थी और फिर खुद को यह बताने के लिए सही किया कि वह तेरह साल की थी। हालांकि उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय चाकू की नोक पर उसकी लज्जा भंग कर दी, लेकिन स्कूल के किसी भी नाम का खुलासा न तो शिकायतकर्ता ने किया है और न ही उसके माता-पिता पीडब्ल्यू 5 और 6 द्वारा। यदि अभियोक्ता किसी स्कूल में पढ़ रहा था तो इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि स्कूल रजिस्टर आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उम्र का प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। पी.डब्ल्यू.10 ने प्रतिपरीक्षा में अभियोक्ता की आयु लगभग पच्चीस वर्ष आंकी। पी.डब्ल्यू.2, अभियोक्ता के चचेरे भाई (भाई) की उम्र लगभग 30 वर्ष थी, ने गवाही दी कि वह उससे छह साल छोटी थी। इस प्रकार अभियोक्ता की उम्र के संबंध में साक्ष्य में व्यापक भिन्नता है। अपर न्यायिक आयुक्त ने अभियोक्ता को चौदह वर्ष की आयु माना और उसके द्वारा दिनांक 18.08.2001 को गवाही में प्रकट की गई आयु के आधार पर अंगूठे के नियम को 20 वर्ष बताया। घटना की तारीख को अभियोक्ता की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, तारीख को उसके अठारह

वर्ष से अधिक आयु के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए।

8. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रकृति में बेहद आकस्मिक और लापरवाह है। अपीलकर्ता से केवल तीन कैप्सूल वाले प्रश्न पूछे गए थे, जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया था: -

"प्रश्न 1। आपके विरुद्ध एक गवाह है कि जब मुखबिर वी. अंशुमाला तिग्गा स्कूल जा रही थी तो आप तोमरा नहर के पास छिपे हुए थे और मुखबिर को एकांत में पाकर आपने उसे चाकू की नोक पर निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रश्न 2. बलात्कार के बाद जब मुखबिर अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित करने के लिए रोते हुए उसके घर दौड़ी और जब मुखबिर के माता-पिता घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए आपके पास आए, तो आपने उनसे कहा कि "अगर मैंने बलात्कार किया है तो मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा"।

प्रश्न 3. आपके निर्देश पर सूचनादाता के माता-पिता ने मुखबिर की "लोटा पानी" रस्म की, जिसमें सूचनाकर्ता के साथ-साथ आपके माता-पिता भी मौजूद थे, उक्त समारोह में आपके माता-पिता ने मुखबिर को एक साड़ी और एक ब्लाउज उपहार में दिया था और सूचना देने वाले के माता-पिता ने आपको कुछ कपड़े भी उपहार में दिए थे" 9. यह अच्छी तरह से तय है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत किसी अभियुक्त को नहीं दी गई परिस्थितियों का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, और इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। एक आपराधिक मुकदमे में, एक अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का महत्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है क्योंकि यह उसे न केवल अपने बचाव को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उसके खिलाफ दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने का भी अवसर प्रदान करता है। एक अभियुक्त द्वारा उठाया एक संभावित बचाव उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के बिना आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है. इस न्यायालय ने बार-बार सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक अभियुक्त से सभी प्रासंगिक प्रश्न पूछने के महत्व पर जोर दिया है। नवल किशोर सिंह बनाम (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य (2004) 7 एससीसी 502 के मामले में यह निष्पक्ष विचारण के अनिवार्य भाग के रूप में निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए आयोजित किया था -

5...... सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों से पूछताछ सबसे असंतोषजनक तरीके से की गई। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी को उसके खिलाफ सबूतों में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने का मौका दिया जाना चाहिए था। कम-से-कम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की विभिन्न मदों को प्रश्नों के रूप में अभियुक्त के समक्ष रखा जाना चाहिए था और उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। इस मामले में आरोपियों को ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया। हम आरोपी के खिलाफ पूरे सबूत को एक ही प्रश्न में एक साथ रखने और उसे समझाने का अवसर देने की प्रथा की निंदा करते हैं, क्योंकि आरोपी तर्कसंगत और बुद्धिमान स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हो सकता है। ट्रायल जज को साक्ष्य में विपरीत परिस्थितियों को समझाने के लिए आरोपी को अवसर देने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए था और धारा 313 की परीक्षा एक खाली औपचारिकता के रूप में नहीं की जाएगी। पूरे सबूत सामने आने के बाद ही आरोपी अपने बचाव को स्पष्ट करने और अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्टीकरण देने की स्थिति में होगा। आरोपी को इस तरह का मौका दिया जाना निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है और अगर यह लापरवाही से किया जाता है, तो इससे सबूतों की सही समझ नहीं हो सकती है.'

10. अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति से संबंधित था जबकि अभियोक्ता ईसाई समुदाय से था। उन्होंने एक पारंपरिक समाज में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार किया। वे दोनों एक ही गांव बसजदी में रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे। आरोपों की प्रकृति और तरीके, उनके बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों के साथ, परीक्षण के दौरान प्रदर्शन के रूप में चिह्नित, यह स्पष्ट करते हैं कि एक-दूसरे के लिए उनका प्यार पर्याप्त समय में बढ़ता और परिपक्व होता गया। वे दोनों एक-दूसरे से प्रभावित थे और युवाओं के जुनून ने उनके दिमाग और भावनाओ पर शासन किया । इसके बाद होने वाले शारीरिक संबंध प्रकृति में अलग-थलग या छिटपुट नहीं थे, लेकिन वर्षों से नियमित थे। अभियोक्ता अपीलकर्ता के घर भी गया था और रहता था। हमारी राय में, अपीलकर्ता द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ अपनी शादी करने से सात दिन पहले एफआईआर दर्ज करने में चार साल की देरी, अभियोजन पक्ष से किए गए वादे के बहाने से सच्चाई और सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

प्रतिपरीक्षा में अभियोक्ता की स्वीकारोक्ति के मद्देनजर मामले की पूरी उत्पत्ति गंभीर संदेह में है कि 09.04.1999 को कोई घटना नहीं हुई थी।

11. अभियोक्ता के माता-पिता, पी. डब्लू 5 और 6 दोनों ने अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें पहली घटना के बाद ही सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना क्यों नहीं दी। इसके विपरीत, पीडब्ल्यू 5 स्वीकार करता है कि अपीलकर्ता ने मंदिर में शादी करने पर जोर दिया, जिसके लिए वे सहमत नहीं थे और चाहते थे कि शादी चर्च में संपन्न हो। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता एक-दूसरे से प्यार करते थे। अभियोक्ता के दावे के विपरीत, पीडब्ल्यू 6 ने कहा कि अभियोक्ता का उसके ही घर में यौन उत्पीड़न किया गया था।

12. अभियोक्ता ने स्वीकार किया कि एक सगाई समारोह भी किया गया था। उसने आगे कहा कि उनके बीच विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों के थे। इसलिए वह इस बाधा के प्रति सचेत थी, भले ही वह अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जारी रखे। अगर अपीलकर्ता ने उससे शादी की होती, तो वह मामला दर्ज नहीं करती। उसने अपीलकर्ता को कोई पत्र लिखने से इनकार किया, जो बचाव पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के विपरीत है। आदान-प्रदान किए गए पत्रों में दोनों द्वारा इस्तेमाल की गई कामुक भाषा से पता चलता है कि अपीलकर्ता रिश्ते के बारे में गंभीर था और शादी में इसे समाप्त करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से सामाजिक कारणों से, विवाह नहीं हो सका क्योंकि वे अलग-अलग समुदायों से थे।

13. हमारे विचार के लिए सवाल यह है कि क्या अभियोक्ता अपीलकर्ता द्वारा शादी के वादे के संबंध में तथ्य की किसी भी गलत धारणा के तहत शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी या उसकी सहमति विवाह की एक धोखाधड़ी गलत बयानी पर आधारित थी, जिसे अपीलकर्ता ने रिश्ते की शुरुआत के बाद से कभी भी रखने का इरादा नहीं किया था। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसने शुरुआत से ही जानबूझकर गलत बयानी की और शिकायतकर्ता ने तथ्य की गलत धारणा पर अपनी सहमति दी, तो धारा 375 आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य की प्रकृति में यह धारण करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसे किसी भी डर के तहत रखकर शुरुआत में

उसकी सहमति प्राप्त की। आईपीसी की धारा 90 के तहत चोट के डर से दी गई सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में हम अभियोक्ता के एकान्त बयान को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि पहले कथित अपराध के समय उसकी सहमति चोट के डर से प्राप्त की गई थी।

14. आईपीसी की धारा 90 के तहत, तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है। लेकिन तथ्य की गलत धारणा घटना के समय के निकट होनी चाहिए और इसे चार साल की अवधि में नहीं फैलाया जा सकता है। यह शायद ही किसी भी विस्तार की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता द्वारा सहमति उचित विचार-विमर्श के बाद उसके द्वारा बनाई गई एक सचेत और सूचित पसंद थी, यह लंबे समय तक फैली हुई थी और विरोध न करने के लिए एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ युग्मित थी। अपीलकर्ता को लिखे अपने पत्रों में अभियोजन पक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि रिश्ते के संबंध में उसके घर पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े होते थे, और उसे पीटा जाता था।

15. उदय (सुप्रा) में, अपीलकर्ता और अभियोक्ता एक ही पड़ोस में रहते थे। चूंकि वे अलग-अलग जातियों के थे, इसलिए वैवाहिक संबंध फलीभूत नहीं हो सके, जबकि विवाह की समझ

> "21. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक राय की आम सहमति इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि अभियोक्ता द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए दी गई सहमति, जिसके साथ वह इस वादे पर गहराई से प्यार करती है कि वह बाद की तारीख में उससे शादी करेगा, तथ्य की गलत धारणा के तहत नहीं दी जा सकती है। एक झूठा वादा संहिता के अर्थ के भीतर एक तथ्य नहीं है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत होने के इच्छुक हैं, लेकिन हमें यह जोड़ना होगा कि यह निर्धारित करने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं है कि क्या अभियोक्ता द्वारा संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है, या क्या यह तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है। अंतिम विश्लेषण में, न्यायालयों द्वारा निर्धारित परीक्षण सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायिक दिमाग को सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन अदालत को, प्रत्येक मामले में, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, उसके समक्ष साक्ष्य और आसपास की

परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस सवाल पर असर डाल सकते हैं कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी, या एक के तहत दिया गया था [**नवीन सिन्हा, जे।** तथ्य की गलत धारणा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबूतों को भी तौलना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक घटक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, सहमति की अनुपस्थिति उनमें से एक है।

16. अपीलकर्ता, उच्च न्यायालय के समक्ष, अपने बचाव में कैनी राजन (सुप्रा) पर भरोसा किया। तथ्य वर्तमान मामले के समान थे। पार्टियों के बीच शारीरिक संबंध शादी करने के वादे की नींव पर स्थापित किया गया था। इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिसमें केपी थिम्मप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, (2011)14 एससीसी 475 भी शामिल था। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने भी इससे निपटने के लिए आवश्यक नहीं समझा, यदि यह संभव था, तो बहुत कम अंतर किया। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उच्चतर न्यायालय की न्यायिक मिसाल का हवाला दिए जाने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने तथ्यों और संबंधित तर्कों के केवल पाठ के बाद, एक अनुच्छेदग्राफ में रहस्यमय रूप से कहा कि साक्ष्य की प्रकृति में, पत्र, अपीलकर्ता की तस्वीर और धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता का बयान, उनकी दोषसिद्धि और सजा में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

17. इस अदालत ने हाल ही में **ध्रुवम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,** एआईआर 2019 एससी 327 और **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, (2019) 9 एससीसी 608 में धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन से उत्पन्न हुई थी, इसी तरह की परिस्थितियों में जहां संबंध एक प्रेम संबंध में उत्पन्न हुआ था, जो शारीरिक संबंधों के साथ समय की अवधि में विकसित हुआ था, प्रकृति में सहमति से, लेकिन विवाह फलीभूत नहीं हो सका क्योंकि पक्षकार विभिन्न जातियों और समुदायों से संबंधित थे, कार्यवाही को रद्द कर दिया और आश्वासन पर उनके बीच शारीरिक संबंध जारी रहे। इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

18. हमने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना विचारशील विचार किया है और इस राय पर विचार किया है कि अपीलकर्ता ने कोई झूठा वादा नहीं किया या जानबूझकर विवाह की गलत बयानी नहीं की, जिससे पक्षों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। अभियोक्ता खुद विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण अपने रिश्ते में बाधाओं से अवगत थी। एक सगाई समारोह भी इस विश्वास में आयोजित किया गया था कि सामाजिक बाधाओं को दूर किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से मतभेद भी पैदा हुए कि क्या विवाह चर्च में या मंदिर में संपन्न होना था और अंततः विफल रहा। उपलब्ध सबूतों पर पकड़ बनाना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने शुरुआत से ही अभियोक्ता से शादी करने का इरादा नहीं किया था और केवल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। अभियोक्ता ने अपने पत्रों में स्वीकार किया कि अपीलकर्ता का परिवार हमेशा उसके लिए बहुत अच्छा था। 493 18. अपीलकर्ता को धारा 420 और 504 आईपीसी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है। आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है, आईपीसी की धारा 341 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, अभियोजन पक्ष के बयान पर विचार करते हुए कि वह अपनी मर्जी से 15 दिनों के लिए अपीलकर्ता के साथ रहने गई थी।

20. हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोक्ता की सहमति एक सचेत और जानबूझकर पसंद थी, जैसा कि एक अनैच्छिक कार्रवाई या इनकार से अलग था और जो अवसर उसके लिए उपलब्ध था, अपीलकर्ता के लिए उसके गहरे बैठे प्यार के कारण उसे स्वेच्छा से उसे अपने शरीर के साथ स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया, जो सामान्य मानव व्यवहार के अनुसार केवल उस व्यक्ति को अनुमति दी जाती है जिसके साथ कोई गहरा प्यार करता है। **उदय** (सुप्रा) में इस संबंध में टिप्पणियों को प्रासंगिक माना जाता है:

> "25... आमतौर पर ऐसे मामलों में ऐसा होता है, जब दो युवा प्यार में पागल होते हैं, कि वे एक-दूसरे से कई बार वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे शादी कर लेंगे। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है, अपीलकर्ता ने भी एक से अधिक अवसरों पर ऐसा वादा किया था। ऐसी परिस्थितियों में वादा सभी महत्व खो देता है, खासकर

जब वे भावनाओं और जुनून से दूर हो जाते हैं और खुद को उन परिस्थितियों और परिस्थितियों में पाते हैं जहां वे कमजोर क्षण में, यौन संबंध बनाने के प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, और अभियोक्ता ने स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ संभोग करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसके साथ वह गहराई से प्यार करती थी, इसलिए नहीं कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था, बल्कि इसलिए कि वह भी ऐसा चाहती थी। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता के ज्ञान को यह बताना बहुत मुश्किल होगा कि अभियोक्ता ने अपने वादे से उत्पन्न तथ्य की गलत धारणा के परिणामस्वरूप सहमति दी थी। किसी भी घटना में, अपीलकर्ता के लिए यह जानना संभव नहीं था कि जब उसने सहमति दी तो अभियोक्ता के दिमाग में क्या था, क्योंकि उसकी सहमति के लिए एक से अधिक कारण थे।

21. निष्कर्ष में, हम अपीलकर्ता की सजा को अस्थिर पाते हैं और इसे अलग करते हैं। अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। उसे निर्देश दिया जाता है कि जब तक किसी अन्य मामले में वांछित न हो, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील की अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।